Commission, a Memorandum of Understanding was signed. This MOU contains decisions taken by the two sides to expand and to further develop bilateral cooperation in various sectors including trade industry, agriculture, transportation and culture.

Protection of interests of Indian citizens working in Gulf-Countries

3663. SHRI MURLIDHAR CHANDRAKANT BHANDARE: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that during the Gulf war, thousands of Indian citizens had to flee from Kuwait, Saudi Arabia and Iraq leaving back their valuables without receiving their legitimate dues from their employers; and

(b) if so, what action is being taken by Government to protect the interests of these citizens in regard to their property and claim?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI R.L. BHATIA): (a) Yes, Sir.

(b) In regard to evacuees from Kuwait and Iraq, Government have set up a Special Kuwait Cell in MEA which is collecting information in the prescribed UN compensation Claim forms which will be lodged with the UN Compensation Commission in Geneva. The first batch of such claims has already been sent to Geneva in December 1992 and the remaining claims when correctly completed in the prescribed forms, will also be forwarded. Government have agreed with the Government of Kuwait in 1991 to facilitate the recovery of assets left behind in Kuwait by means of a Power of Attorney, which in Arabic and English, had been given wide publicity.

Regarding Saudi Arabia, our Embassy have provided assistance when requested to a number of Indian nationals for settlement of their dues from their employers and regarding the property they had left behind.

As a result of Government's diplomatic efforts, majority of Indian nationals have already gone back to Kuwait.

पंजाब और जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद के प्रति अमरीकी दृष्टिकोण

3664. **श्री अनन्त राम जायसवाल:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि अमरीका सरकार ने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि पाकिस्तान कश्मीर और पंजाब के आतंकवादियों को प्रशिक्षण, हथियार और धन उपलब्ध करा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या भारत सरकार ने अमरीका द्वारा पाकिस्तान को उग्रवादी/आतंकवादी देश घोषित करने के लिये कोई कार्यवाही की है, यदि हां, तो कब और इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फेलेरियो): (क) और (ख) पैटर्न ऑफ ग्लोबल टैररिज्म 1991 पर अमरीका के विदेश विभाग ने प्रकाशित की गई अपनी रिपोर्ट में यह कहा था कि: "1991 के वर्ष भर ऐसी विश्वसनीय रिपोर्टें मिलती रही हैं कि भारत-नियंत्रित कश्मीर में आतंकवाद में लगे कश्मीरी सैन्य ग्रुपों और भारत के पंजाब क्षेत्र में आतंकवाद में लगे सिख उग्रवादी ग्रुपों को भी पाकिस्तान की ओर से सरकारी तौर पर मदद मिलती रही है। इस मदद में कथित रूप से शस्त्र और प्रशिक्षण की व्यवस्था शामिल है।"

(ग) पंजाब और जम्मू तथा कश्मीर में आतंकवाद को पाकिस्तान के समर्थन पर सरकार ने अमरीका की सरकार को बार-बार अपनी गंभीर चिन्ता से अवगत कराया है। सरकार ने अमरीका की सरकार को भारत में आतंकवादी ग्रुपों के साथ पाकिस्तान के होने के विस्तृत साक्ष्य भी उपलब्ध कराए हैं।